जैसे अधिकांश उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है ; यदि हां, तो उनके नाम, पद तथा पतों सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जिन्होंने इस कार्यवाही पर अमल किया है तथा उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार भविष्य में उक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने तथा उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन जातियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इन जातियों के कल्याण हेतु विशेष आयुक्त को विशेष शक्तियां प्रदान करने का विचार रखती है ताकि वे न्याय प्राप्त कर सकें ; यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कार्यालय में अधिकारियों के नाम और पदनाम इस प्रकार हैं :—

1. डा० वी० डी० शर्मा, विशेष अधिकारी तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ।

2. श्री आर० पी० कपिला, अनुसूचित जनजाति विशेष आयुक्त, और

3. श्री एल.एन. गुप्ता, अनुसूचित जाति विशेष आयुक्त ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त कार्यालय में उपायुक्त के दो पद हैं जिनमें से एक रिक्त है तथा एक अन्य पर अनुसूचित जाति सदस्य कार्य कर रहा है ।

आयुक्त तथा विशेष आयुक्तों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त अनेक शिकायतें संबंधित विभागों/एजेंसियों को भेजी जा रही है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में, की गई कार्रवाई के परिणाम मोटे तौर पर दिए गए हैं ।

संविधान के अनुछेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । विशेष आयुक्तों की तैनाती कार्मिक विभाग द्वारा की जाती है । अन्य अधिकारी कल्याण मंत्रालय द्वारा तैनात किए जाते हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तैनात करने की सरकार की नीति नहीं है । तथापि, विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों की तैनाती का ध्यान रखा जाता है ।

NDDB's Technical Cooperation with the FAO

407. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any agreement has been signed by Government with the Food and Agriculture Organisation concerning technical co-operation with the National Dairy Development Board ; and

(b) if so, the terms and conditions thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) : (a) and (b) Yes, Sir. An agreement between Government of India and Food and Agriculture Organisation (FAO) was signed on 8th February, 1990 covering US $ one million under the Funds-in-Trust arrangement. Under this agreement, FAO shall be responsible for provision of experts, consultants, training and equipment to the National Dairy Development Board for implementation of Operation Flood-III.

Augmenting the water supply in tail-end colonies of South Delhi

408. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in spite of many steps announced by Government and the MCD for augmenting the water supply, adequate water supply has still not been ensured in the South Delhi's tail-end colonies;

(b) if so, what are the reasons therefor ;

(c) what steps are being taken to ensure adequate supply of water to these colonies ;

(d) the total requirement of water of the Government colony Vasant Vihar;

(e) the quantity of water promised to be supplied by MCD and the quantity actually being supplied presently to this colony per day ; and

(f) the steps being taken to ensure supply of promised quantity of water ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) : (a) to (c) The colonies in South Delhi are at the tail end of the water distribution system, since the treatment plants are located in North, North-East and North-West of Delhi. Water is carried through rising mains over a distance of 15 to 20 kms. Thus even minor break downs in the transmission system have repercussions in the supply at the tail-end. However, the position has improved as a result of certain measures taken during 1989-90, which includes construction of ground reservoir and booster pumping station at Deerpark, energisation of 24 new tubewells, re-development and energisation of 18 old tubewells and commissioning of newly laid water mains from Jhandewalan to Palam reservoir etc.

(d) to (f) The total requirement of water of the Government colony in Vasant Vihar is about 4.54 million litres a day and this is being fully met.

Purchase of surplus milk

409. CHOWDHRY HARI SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the surplus production of milk in Western Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan which is not being taken or purchased by the Agriculture Department or by the societies patronised by Agriculture Department; and

(b) if so, what action Government propose to take to purchase the surplus milk produced by the above milk producers ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) and (b) Government are aware of increased availability